विचार बिन्दु

अगर तुम गलतियों को रोकोगे, तो भी सत्य बाहर आ जायेगा। –टैगोर

भारतीय अर्थव्यवस्था परवान चढ़ती हुई या मरी हुई!

हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक विवादास्पद टिप्पणी की जिसमें उन्होंने कहा कि ''भारतीय अर्थव्यवस्था मरी हुई है''। विपक्ष के नेता ने मरी हुई अर्थव्यवस्था का शब्द अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बयान से लिया था जिसमें भारत और रूस के बीच घनिष्ठ संबंधों को लेकर तीखा हमला बोला गया था और कहा गया था कि भारत और रूस दोनों देश मिलकर अपनी ''मृत अर्थव्यवस्थाओं'' को गर्त में ले जा रहे हैं। राहुल गांधी का ट्रम्प की टिप्पणी को समर्थन करता यह कथन न केवल राजनीतिक दृष्टि से तीखा था, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी अनेक बहसों को जन्म देने वाला साबित हुआ। यहां यह सवाल भी स्वाभाविक रूप से उठा कि क्या विपक्ष के नेता का यह बयान एक राजनीतिक अतिशयोक्ति है या इसके पीछे ठोस तथ्य और आंकड़े भी मौजूद हैं? बेहतर होता विपक्ष के नेता अपने कथन को साबित करने वाले तथ्य भी साथ में देते। मीडियाकर्मियों ने भी उनसे उसी प्रकार कोई उलट सवाल नहीं किया जिस प्रकार के सवाल नहीं करने के आरोप प्रधानमंत्री समर्थक मीडिया पर उठते आए हैं। राहुल गांधी का यह बयान ऐसे समय आया है जब विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार केवल आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है, जबकि आम जनता की स्थिति दिन-ब-दिन बदतर होती जा रही है। हालांकि राहुल गांधी अक्सर सरकार की आर्थिक नीतियों पर प्रश्न उठाते रहे हैं, लेकिन उनका देश की अर्थव्यवस्था को ''मरी हुई अर्थव्यवस्था'' कहना एक गंभीर आरोप है, जिसका अर्थ यह है कि अर्थव्यवस्था न केवल संकट में है बल्कि उसमें सुधार की गुंजाइश भी नगण्य हैं। राजनीतिक दृष्टि से यह बयान उस राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है जिसमें एक ऐसा प्रहार है जो जनता को सोचने पर मजबूर करे कि 'अमृतकाल' और '5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी' की बातें ज़मीनी हकीकत से कितनी मेल खाती हैं। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के इस बयान को लेकर दो प्रकार की अपेक्षित प्रतिक्रियाएं आई हैं। एक वर्ग ने उन्हें 'नकारात्मक मानसिकता' वाला कहा, तो दूसरे ने कहा कि ''कम से कम कोई तो ज़मीन की बात कर रहा है।'' लेकिन यह भी दिलचस्प है कि राहुल गांधी की पार्टी के ही दो वरिष्ठ नेताओं शशि थरूर और राजीव शुक्ला ने बयान दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है और अच्छा प्रदर्शन कर रही है।

सरकारी दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत एक मजबूत और संभावनाओं से भरी अर्थव्यवस्था है, जो वैश्विक आर्थिक मंदी के बीच भी स्थिरता बनाए हुए है। सरकार के समर्थकों का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ''मृत अर्थव्यवस्था'' होने से कोसों दूर है। वास्तव में, यह अपनी गतिशील और अपनी विविधता वाली संरचना के साथ, विश्व स्तर पर सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। वे मजबूत विकास दर के आकड़ों का हवाला देते हैं। जैसे वित्त वर्ष 23/24 में भारत की जीडीपी में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिससे यह विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गई। इसका श्रेय सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में निवेश, रियल एस्टेट में घरेलू निवेश तथा साथ में 9.9 प्रतिशत की तेज वृद्धि से बढ़ते विनिर्माण क्षेत्र को दिया जाता है। वित्त वर्ष 2026 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.4 से 6.8 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है, जबकि अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने इसके 6.3 प्रतिशत से 6.8 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान लगाया है। भारत वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के हिसाब से पांचवी सबसे बड़ी और क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका सकल घरेलू उत्पाद वित्त वर्ष 2025 में 3.82 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। इसके 2025 में इसके जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है और 2027-2030 तक इसके तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है।

आर्थिक विकास को गति देने वाले प्रमुख क्षेत्र में सेवा क्षेत्र सबसे बड़ा है जो सकल घरेलू उत्पाद में 60 प्रतिशत का योगदान देता है। इसमें आईटी, वित्त और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग प्रमुख है। भारत के आईटी-बीपीएम क्षेत्र का 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद में 10 प्रतिशत योगदान होने का अनुमान है, जिसका 80 प्रतिशत राजस्व निर्यात से आएगा। इसी प्रकार विनिर्माण क्षेत्र में वित्त वर्ष 25 में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसे निजी निवेश और मेक इन इंडिया जैसी सरकारी पहलों का समर्थन मिला। निर्यात को देखें तो वित्त वर्ष 2025 में वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्यात 5.5 प्रतिशत बढ़कर 820.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो भारतीय उत्पादों की वैश्विक मांग को दर्शाता है। नवीकरणीय ऊर्जा को लें तो भारत 2025 तक अमेरिका और पश्चिम एशिया के साथ 100 गीगावाट की अनुमानित क्षमता के साथ, महत्वपूर्ण सौर क्षमता जोड़ रहा है। मगर जहां जीडीपी वृद्धि दर ऊंची है, वहीं कुछ बिंदु राहुल गांधी के बयान को जरूर प्रासंगिक बना सकते हैं जैसे बेरोजगारी की स्थिति। सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन ईकानमी के अनुसार, भारत में बेरोजगारी दर 7 प्रतिशत से ऊपर बनी हुई है। युवाओं में बेरोजगारी की दर तो और भी अधिक है, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में। स्नातकों और शिक्षित युवाओं के लिए अवसरों की कमी एक गहरा संकट है। जीडीपी बढ़ती है, लेकिन रोजगार क्यों नहीं बढ़ते – यह प्रश्न बेहद गंभीर है। इसी प्रकार भले ही सरकार कहे कि मुद्रास्फीति नियंत्रण में है, लेकिन आम जनता के लिए रसोई गैस, पेट्रोल, खाद्य वस्तुएं, दवाइयां और शिक्षा जैसी बुनियादी चीजों पर खर्च भारी पड़ रहा हैं। ऐसी स्थिति में लोगों को सुहावने आर्थिक आंकड़े खोखले लगने लगते हैं और विपक्ष के नेता की अतिशयोक्ति वाली टिप्पणी बहुतों को भाने लगती है।

> **एक वर्ग ने उन्हें 'नकारात्मक मानसिकता' वाला कहा, तो दूसरे ने कहा कि ''कम से कम कोई तो ज़मीन की बात कर रहा है।'' लेकिन यह भी दिलचस्प है कि राहुल गांधी की पार्टी के ही दो वरिष्ठ नेताओं शशि थरूर और राजीव शुक्ला ने बयान दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है और अच्छा प्रदर्शन कर रही है।**

उधर ऑक्सफाम की रिपोर्ट भारत में आर्थिक असमानता की बात करती है। वह कहती है कि कुल राष्ट्रीय संपत्ति का बड़ा हिस्सा कुछ प्रतिशत अमीरों के पास केंद्रित है। यदि आर्थिक विकास केवल कुछ लोगों को ही समृद्ध बनाए और बाक़ी देश हाशिये पर रहे, तो उसे 'मृतप्राय:' कहना बहुतों को अतिशयोक्ति नहीं लगता। अनेक अर्थशास्त्री भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारत में विकास हो रहा है, लेकिन वह असंतुलित है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक जैसी एजेंसियां भारत की विकास दर को सराहते हुए भी बार-बार इस पर ज़ोर देती हैं कि सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भारी निवेश आवश्यक है ताकि देश की आबादी में आर्थिक असामानता कम हो सके।

यह जरूर है कि राहुल गांधी का ''मरी हुई अर्थव्यवस्था'' वाला बयान भाषाई दृष्टि से अत्यंत आक्रामक है। इसमें अतिशयोक्ति अवश्य है क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था मरी हुई तो कत्तई नहीं है – वह गतिमान है, बढ़ रही है, और कुछ क्षेत्रों में तेज़ी से भी बढ़ रही है। लेकिन यह भी सच है कि देश की बड़ी आबादी उस विकास को महसूस नहीं कर पा रही है। राहुल गांधी का बयान उसी भावना को उजागर करता है जिसे लाखों लोग रोज़ अनुभव करते हैं: नौकरी नहीं मिल रही, छोटा व्यापार नहीं चल रहा, महंगाई बढ़ रही है। राहुल गांधी का यह बयान राजनीतिक रूप से भले ही उत्तेजक हो, लेकिन वे इस चौकाने वाली टिप्पणी से उस गहरी वास्तविकता की ओर इशारा करते हैं जिसमें भारत में आर्थिक विकास और आम आदमी के अनुभव के बीच एक बड़ी खाई है। भारत की अर्थव्यवस्था तकनीकी रूप से जीवंत है, लेकिन जब वह करोड़ों लोगों को न्यूनतम गरिमा का भाव और अवसर नहीं दे पाए, तो उसके 'जीवंत' होने पर सवाल उठना स्वाभाविक ही है। सच्चाई शायद राहुल गांधी के शब्दों और सरकारी आंकड़ों के बीच कहीं है। भारत को केवल विकास नहीं, समावेशी और न्यायपूर्ण विकास की आवश्यकता है। जब तक आम जनता को आर्थिक सुरक्षा और अवसर नहीं मिलते, तब तक जीडीपी के आंकड़े सिर्फ़ कागज़ी विजय लगेंगे – जमीनी सच्चाई नहीं। इसलिए यदि भारत को वास्तव में 'विकासशील' से 'विकसित' राष्ट्र बनाना है, तो उसे सिर्फ़ जीडीपी वृद्धि पर ही पर्याप्त नहीं, बल्कि समावेशी विकास, रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय व्यवस्था पर भी ध्यान देना होगा। सिर्फ पूंजी निवेश और निजीकरण से समस्याएं नहीं सुलझेंगी। इसके लिए सबसे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को निजी क्षेत्र में धकेलने की अंधी दौड़ से बाहर आना होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य की सुदृढ़ सार्वजनिक सेवाओं की गिरावट के दौर में सरकार को ऐसे उलाहने झेलने पड़ेंगे। देश की अर्थव्यवस्था आमजन को तभी जीवंत लग सकती है जब उनकी भी उसमें बराबरी की भागीदारी हो। इसके लिए सभी प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को सुधारना होगा जो वर्तमान में आकंठ भ्रष्टाचार के दलदल में धंसी हुई है। कार्यपालिका लोकतंत्र का प्रमुख स्तम्भ है। वही लोकनीतियों का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के लिए ज़िम्मेदार है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है। मगर विधायिका सिर्फ संसदीय सत्ता की प्रतिस्पर्धी राजनीति में सिमट कर रह गई है और सारे राजनेता एक-दूसरे को नीचा दिखाने और खिल्ली उड़ाने के खेल में लगे हैं। राजनेता भी भ्रष्टाचार की कालिख से अछूते नहीं रहे हैं। राजनेताओं को देश की समस्याओं और गरीबी का कुछ भान भी है ऐसा लगता ही नहीं। अर्थव्यवस्था भले ही जीवंत और लचीली है और उसमें विकास की मज़बूत संभावनाएं हैं मगर प्रशासनिक तंत्र तथा राजनीतिक व्यवस्थाएं लोगों को उसे महसूस नहीं होने देती। जब कोई राजनेता ''मृत अर्थव्यवस्था'' जैसा आरोप लगाता है, जो भले ही साक्ष्य समर्थित नहीं हो, तब भी वह झंझोड़ कर जगाने वाला जरूर होता है जिसे बहुत से लोग देश के लिए अपमानजनक मान लेते हैं।

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

सरकारी स्कूल तभी सुधरेंगे, जब सरकारी कर्मचारी अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में भेजेंगे

अशोक कुमार

एक ओर हम डिजिटल युग की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं और विश्व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कदम रख चुका है, वहीं हमारे सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। देश के हजारों जर्जर स्कूल के कारण बच्चों की जान पर खतरा मंडरा रहा है! हजारों स्कूल बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। कहीं भवन जर्जर हैं तो कहीं बिजली, फर्नीचर और शौचालय की सुविधा नहीं है।

राजस्थान के झालावाड़ जिले में हाल ही मे एक सरकारी स्कूल की इमारत का एक हिस्सा ढहने से सात बच्चों की मौत हो गई और 28 अन्य घायल हो गए। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का कौन जिम्मेदार है?

Unified District Information System for Education (UDISE) के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में केवल 57.2% सरकारी स्कूलों में ही कंप्यूटर उपलब्ध हैं और सिर्फ 53.9% स्कूलों में इंटरनेट कनेक्शन है। हालांकि, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, 90% से अधिक स्कूलों में बिजली और शौचालय की सुविधाएं हैं, लेकिन सिर्फ 52.3% स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप की व्यवस्था है। कम होता नामांकन और बढ़ता ड्रॉपआउट रेट।

सरकारी स्कूलों में छात्रों के नामांकन में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 2023-24 में, सरकारी स्कूलों में कुल छात्रों की संख्या में 37 लाख की कमी आई है। जहां देश की आबादी और गरीबी दोनों बढ़ रही हैं, लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने से कतराने लगे हैं। योग्य और पर्याप्त शिक्षक नहीं।

सरकारी स्कूलों में शिक्षक तो हैं, लेकिन उनकी योग्यता और संख्या पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं, जो शिक्षक हैं उनमें से बड़ी संख्या में उनकी शैक्षणिक योग्यता मानकों पर खरी नहीं उतरती। परिणामस्वरूप, छात्रों की पढ़ाई और प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

नई शिक्षा नीति 2020 के बावजूद गिरावट

नई शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) का उद्देश्य शिक्षा के स्तर में सुधार करना था। लेकिन, इसके बावजूद सरकारी स्कूलों के आंकड़े और गिरावट की ओर इशारा कर रहे हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी डिजिटल सुविधाएं अधिकांश स्कूलों में उपलब्ध नहीं हैं। बच्चों के नामांकन और ड्रॉपआउट दर में गिरावट ने नीति के उद्देश्यों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

क्या सरकारी शिक्षा विभाग सिर्फ एक एजेंसी बनकर रह जाएगा?

अगर सरकारी स्कूलों की यह स्थिति जारी रही, तो आने वाले वर्षों में शिक्षा विभाग केवल एक परीक्षा आयोजित करने वाली और प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देने वाली एजेंसी बनकर रह जाएगा। सरकारी स्कूलों का मूल उद्देश्य – शिक्षा प्रदान करना – धीरे-धीरे समाप्त होता दिख रहा है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने 18 अगस्त 2015 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। यह फैसला शिव कुमार पाठक और कई अन्य लोगों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई के दौरान आया था। अदालत ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सरकारी कर्मचारी, निर्वाचित प्रतिनिधि और न्यायपालिका के सदस्य अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में भेजें। यह आदेश उन सभी व्यक्तियों पर लागू होता था ''जो राज्य के खजाने या सार्वजनिक धन से कोई लाभ, सुविधा, वेतन आदि प्राप्त करते हैं''।

अदालत ने सरकारी स्कूलों की 'दयनीय स्थिति' पर गंभीर चिंता व्यक्त की और इसका कारण ''प्रशासन की वास्तविक भागीदारी की कमी'' बताया। फैसले का मुख्य तर्क यह था कि यदि अधिकारियों और राजनेताओं को अपने बच्चों को इन स्कूलों में भेजने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वे स्कूलों की आवश्यकताओं को गंभीरता से देखेंगे और उनकी अच्छी स्थिति सुनिश्चित करेंगे। इससे स्कूलों में जवाबदेही और निगरानी बढ़ेगी।

न्यायमूर्ति अग्रवाल ने यह भी टिप्पणी की कि यह कदम विभिन्न सामाजिक वर्गों के बच्चों को एक-दूसरे के साथ बातचीत करने और घुलने-मिलने का अवसर देगा, जिससे ''समाज को जमीनी स्तर पर बदलने में क्रांति'' आएगी और आम आदमी के बच्चों को आत्मविश्वास और अन्य अवसर मिलेंगे। अदालत ने प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्तियों में राजनीतिक कारणों से रिक्तियों को बनाए रखने और अक्षम व्यक्तियों को नियुक्त करने जैसे मुद्दों पर भी प्रकाश डाला, जिससे शिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित हुई।

अदालत ने आदेश का उल्लंघन करने वालों के लिए दंडात्मक प्रावधानों का भी उल्लेख किया। यदि कोई बच्चा निजी स्कूल में भेजा जाता है, तो माता-पिता द्वारा उस बच्चे के लिए भुगतान की जा रही फीस के बराबर राशि उनके मासिक वेतन से काट ली जाएगी। इसके अतिरिक्त, ऐसे व्यक्ति को ''वेतन वृद्धि, पदोन्नति के अवसर जैसे अन्य लाभों से भी वंचित किया जा सकता है''। एकत्रित राशि का उपयोग सरकारी स्कूलों के सुधार के लिए किया जाना था।

उपलब्ध जानकारी के आधार पर, सरकारी कर्मचारियों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने के लिए अनिवार्य करने वाला इलाहाबाद हाईकोर्ट का 2015 का फैसला प्रभावी ढंग से लागू नहीं हुआ!

यह फैसला, हालांकि लागू नहीं हुआ, सार्वजनिक शिक्षा की बिगड़ती स्थिति और अधिकारियों के 'पाखंड' के खिलाफ एक शक्तिशाली प्रतीकात्मक बयान के रूप में कार्य करता है। इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित करना जरूरी है! इससे मीडिया और सार्वजनिक विमर्श में सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता, लोक सेवकों की जवाबदेही और शैक्षिक असमानता के बारे में एक तीखी बहस छेड़नी चाहिए। इस विशिष्ट जनादेश के गैर-कार्यान्वयन ने सरकार को सार्वजनिक शिक्षा में सुधार के लिए वैकल्पिक रणनीतियों का पता लगाने के लिए प्रेरित होना चाहिए! सरकारी स्कूलों में खराब बुनियादी ढांचे, बुनियादी सुविधाओं की कमी, शिक्षकों की रिक्तियों और शिक्षण की गुणवत्ता के अंतर्निहित मुद्दे अभी भी बने हुए हैं, यह दर्शाता है कि जिन मुख्य समस्याओं को फैसले ने संबोधित करने की कोशिश की थी, वे इस विशिष्ट तंत्र के माध्यम से काफी हद तक अनसुलझी रही हैं।

2015 के फैसले को एक ''ऐतिहासिक फैसला'' के रूप में सराहा गया था, जिसका इरादा 'सही' था, फिर भी इसे प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया। यह ''अप्रवर्तित ऐतिहासिक'' फैसलों की एक श्रेणी बनाता है – वे जो अपने कानूनी घोषणाओं और सामाजिक इरादों में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कार्यान्वयन अंतराल के कारण ठोस परिवर्तन में विफल रहते हैं। यह न्यायिक घोषणाओं और वास्तविक शासन के बीच के अंतर को उजागर करता है। एक अदालत एक साहसिक आदेश जारी कर सकती है, लेकिन इसका वास्तविक दुनिया का प्रभाव राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक क्षमता और सामाजिक स्वीकृति पर निर्भर करता है। यह भी सुझाव देता है कि कुछ न्यायिक हस्तक्षेप, हालांकि कागजों पर शक्तिशाली होते हैं, जटिल सामाजिक-राजनीतिक वातावरण में बहुत महत्वाकांक्षी या लागू करने में मुश्किल हो सकते हैं।

–अशोक कुमार,
पूर्व कुलपति कानपुर, गोरखपुर विश्वविद्यालय, विभागाध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

उत्तर-पश्चिम रेलवे ने अस्तित्व में आने के बाद भारतीय रेलवे में अलग पहचान बनाई

अपनी स्थापना से 22 वर्षों के सफर में उत्तर-पश्चिम रेलवे आज देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक, औद्योगिक विकास में भागीदार बनकर महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है

वेदप्रकाश

उत्तर-पश्चिम रेलवे 1 अक्टूबर, 2002 को अस्तित्व में आने के बाद आज भारतीय रेलवे में अलग पहचान बना चुका है। उत्तर-पश्चिम रेलवे के चारों मण्डल जयपुर, जोधपुर, अजमेर एवं बीकानेर पर्यटन, औद्योगिक, सामरिक एवं सामाजिक रूप से विशेष महत्व रखते हैं। अपनी स्थापना से 22 वर्षों के सफर में उत्तर-पश्चिम रेलवे आज देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक तथा औद्योगिक विकास में भागीदार बन कर महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है।

उत्तर-पश्चिम रेलवे का क्षेत्राधिकार राजस्थान के प्रमुख पर्यटकों स्थलों के साथ सम्पर्क स्थापित करता है। रेलवे द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विरासत के साथ-साथ विकास को आधार बना कर कार्य किए जा रहे हैं। रेलवे पर्यटन स्थलों तक पहुंच के मामले में सबसे सुविधाजनक, रोमांचकारी और सुरक्षित साधन होने के साथ ही स्वयं भी पर्यटन का केन्द्र है। उत्तर-पश्चिम रेलवे द्वारा हैरिटेज संरक्षित करने और इसको आमजन तक पहुंचाने के लिए विशेष पहल की जा रही है जिससे आमजन को सांस्कृतिक व समृद्ध विरासत से परिचय करवाया जा सके।

इसी कड़ी में अरावली की सुरम्य पहाड़ियों में आजादी से पूर्व बनी मारवाड़-खामली घाट रेल खंड को विरासत के रूप में संरक्षित के लिए मीटर गेज ही रखा गया है। इस खण्ड पर मारवाड़ खामली घाट-मारवाड़ के बीच प्रदेशकी पहली हेरिटेज ट्रेन वैली क्वीन संचालित की जा रही है।

इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 05 अक्टूबर 2023 को हरी झंडी दिखाकर किया गया। वैली क्वीन हेरिटेज ट्रेन में एक वातानुकूलित चेयर कार एवं एक पॉवर कार कोच के साथ एक डीजल इंजन को भाप इंजन जैसा बनाया गया है। यात्रा में यात्रियों को हरी-भरी घाटियों,पहाड़ियों, दुर्लभ वनस्पतियों और स्थानीय जीव जन्तुओं के मनमोहक दृश्य देखने को मिलते हैं। इस मार्ग में लगभग 100 साल पुरानी दो सुरंगें और जलधाराओं पर 172 पुल हैं।

ट्रेन के कोच में एनाउंसमेंट के साथ टीवी स्क्रीन भी लगाई गई है जिसमें पूरे मार्ग एवं गोरमघाट की वादियों के बारे में पर्यटकों को जानकारी दी जाती है। पूरे दिन की यात्रा में यात्रियों को प्राकृ तिक सौदर्य एवं रोमांच का अनुभव प्राप्त होता है।

इसके अतिरिक्त अजमेर मंडल की ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने व आमजन को भारतीय रेल की समृद्ध विरासत से परिचित करवाने के लिये अजमेर में रेलवे संठाहालय स्थापित किया गया है। अजमेर मंडल की ऐतिहासिक विरासत को और संरक्षित करने व आमजन को भारतीय रेल की समृद्ध विरासत से रूबरू करवाने के लिए अजमेर में नसीराबाद रोड पर रेलवे संग्रहालय स्थापित किया गया है, जो लगभग 16000 वर्ग मीटर परिसर में फैला है।

नसीराबाद रोड, मार्टिण्डल ब्रिज समीप स्थित यह रेल संग्रहालय स्थानीय और अजमेर आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है और इसे अजमेर का नया टूरिस्ट पॉइंट भी कहा जा सकता है। रेल म्यूजियम में अजमेर मंडल सहित भारतीय रेल की महान ऐतिहासिक व समृद्धिवरासत से परिचय कराया गया है। रेल संग्रहालय परिसर में आकर्षण का केंद्र एक टॉय ट्रेन है जिसके लिए मीटर गेज का ट्रैक बिछाया गया है। इस टॉय ट्रेन को मीटर गेज की 5 पुश ट्रॉलियों से बनाया गया है। रेल म्यूजियम में 3 डी प्रभावों के साथ कैनवास पर बनाई गई सिनोग्राफी, साइनेज, सबसे पुराने भाप इंजन का मॉडल, राजस्थान के तीर्थ स्थानों के मार्ग, ''रेलवे की प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग'' आदि पर आधारित इंटरैक्टिव मॉडल सहित अन्य ऐतिहासिक महत्व की वस्तुएं प्रदर्शित की गयी है।

पैलेस ऑन व्हील्स भारत की पहली लक्जरी पर्यटक ट्रेन है जिसे भारतीय रेलवे ने राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान पर्यटन विकास निगम (आरटीडीसी) के संयुक्त सहयोग से संचालित किया जा रहा है। यह ट्रेन दिल्ली से प्रारम्भ होकर जयपुर, रणथम्बोर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर होते हुए आगरा पहुंचती है।

प्रत्येक कोच का नाम पूर्व रियासतों के नाम पर अलवर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, धौलपुर, डूंगरगढ़, जैसलमेर, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर, किशनगढ़, कोटा, सिरोही और उदयपुर रखा गया है। ट्रेन में महाराजा और महारानी दो रेस्तरां बनाए गए हैं, जिनमें स्वादिष्ट राजस्थानी और कॉन्टिनेंटल व्यंजन परोसे जाते हैं।

अब बात करें रेल से दिखने वाली विश्व प्रसिद्ध सांभर झील की। राजस्थान में जयपुर के समीप स्थित सांभर में लवण जल (खारे पानी) की झील है। यह झील समुद्र तल से 1,200 फुट की ऊँचाई पर स्थित है। जब यह भरी रहती है तब इसका क्षेत्रफल 90 वर्ग मील रहता है। इसमें चार नदियाँ (रुपनगढ, मेंथा, खारी, खंड़ेला) आकर गिरती हैं। इस झील से बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन किया जाता है।

यह झील उत्तर-पश्चिम रेलवे के जयपुर एवं जोधपुर मण्डल को जोड़ने वाले प्रमुख रेल मार्ग जयपुर-फुलेरा-मेडता-जोधपुर के अंतर्गत आती है। रेलवे लाइन इस झील को लगभग 2 भागों में बांटती है। इस झील के मध्य से गुजरती रेल लाइन से मनमोहक नजारा दिखता है एवं यह पर्यटकों के मध्य खासा लोकप्रिय रेलमार्ग है।

भारतीय रेलवे वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण ''एक स्टेशन-एक उत्पाद'' योजना स्थानीय लोगों को स्वदेशी उत्पाद बेचने के लिए विशिष्ट रूप से डिज़ाइन किए गए बिक्री आउटलेट प्रदान करती है। स्थानीय कलाकारों, उद्यिमयों, बुनकरों एवं छोटे व्यवसाईयों को मंच प्रदान करने के लिए रेलवे स्टेशनों पर ''एक स्टेशन-एक उत्पाद''योजना की शुरुआत की गई है।

इस योजना से स्थानीय लोक कला के कारीगरों को लाभ तो मिल ही रहा है साथ ही रेल यात्रियों को स्टेशन पर ही स्थानीय उत्पाद मिल रहे है। इस योजना में वर्तमान में उत्तर-पश्चिम रेलवे पर जयपुर में सांगानेरी प्रिंट के कपडे, अजमेर में गुलाब से बने उत्पाद, उदयपुर में हस्तनिर्मित लकड़ी के खिलोने, जोधपुर में हेंडीक्राफ्ट आइटम खासे लोकप्रिय हो रहे हैं।

उत्तर-पश्चिम रेलवे पर 77 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किया जा रहा है। स्टेशनों के पुनर्विकास में स्थानीय कला के अनुरूप हैरिटेज को ध्यान में रखकर आधुनिकता का समावेश किया जा रहा है। स्टेशनों के पुनर्विकास से स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को उच्चस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होगी और उनको सुखद अनुभूति मिलेगी। स्टेशनों के पुनर्विकास की परिकल्पना में इस विषय पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है कि इसे सिटी सेन्टर के रूप में विकसित किया जाएगा जिससे यह यात्रियों के साथ-साथ शहर के निवासियों के भी आकर्षण का केन्द्र बने।

अजमेर में स्थापित रेल कारखाना 1876 में प्रारम्भ किया गया था, यह भारत के प्रमुख कारखानों में से एक है। यह मीटरगेज डीजल लोको का सबसे बडा कैरिज और वैगन कारखाना था। वर्तमान में ब्रॉडगेज रोलिंग स्टॉक के प्रमुख मदो कोच, वैगन, डीईएमयू, रेल बस आदि का अनुरक्षण कर सेवाएं प्रदान कर रहा है। इस कारखाना की बिल्डिंग हैरिटेज को दर्शाती है और यह प्रदर्शित करती है कि वह लम्बे समय से मजबूती के साथ रेलवे के रोलिंग स्टॉक के अनुरक्षण में अहम भूमिका का निर्वहन कर रहा है।

गडरा रोड, राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण गांव है, जो ऐतिहासिक, सांतिक और सामरिक दृष्टि से विशेष पहचान रखता है। यह गांव पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है और भारतीय रेलवे के पश्चिमी छोर पर स्थित है। 1965 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने बाड़मेर जिले में भारतीय रेलवे ट्रैक पर बमबारी की थी, जिसके माध्यम से सेना को रसद पहुंच रही थी। इस बमबारी से रेलवे ट्रैक को बहुत क्षित हुई और सेना को रसद की आपूर्ति बंद हो गई।

इस स्थिति में रेलकर्मियों ने अपने जान का परवाह न करते हुए रेल सम्पर्क स्थापित करने के लिए बमबारी के बावजूद रेल ट्रैक का ठीक कर रेल संचालन को प्रारम्भ किया। भारत का पहला रेलवे शहीद स्मारक 1965 में भारत-पाक युद्ध में जान गंवाने वाले 17 रेल कर्मचारियों को समर्पित बाड़मेर जिले के गडरा रोड स्टेशन पर स्थापित किया गया है। राजस्थान में भारत-पाक सीमा पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले रेलवे कर्मचारियों के लिए शहीद स्मारक बनाया गया।

रेलवे पर्यटन और स्थानीय लोक कला को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें नवाचारों को सम्मलित कर नई संभावनाओं पर भी निरंतर कार्य कर रहा है। रेलवे उन क्षेत्रों की भी पहचान कर रहा है जहाँ हैरिटेज संरक्षण किया जा सके और आमजन को उस गौरवशाली अतीत से रूबरू करवाया जा सके।

वेदप्रकाश, सेवानिवृत मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, उत्तर-पश्चिम रेलवे।

राशिफल

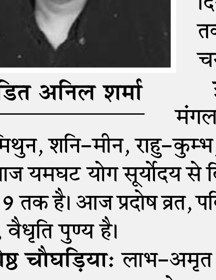

पंडित अनिल शर्मा

बुधवार 6 अगस्त, 2025

सावन मास, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2082, मूल नक्षत्र दिन 1:00 तक, वैधृति योग प्रात: 7:17 तक, बरलव करण दिन 2:09 तक, चन्द्रमा आज धनु राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कर्क, चन्द्रमा-धनु, मंगल-कन्या, बुध-कर्क, गुरू-मिथुन, शुक्र-मिथुन, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज यमघट योग सूर्योदय से दिन 1:00 तक है। राजयोग दिन 1:00 से 2:09 तक है। आज प्रदोष व्रत, पवित्र बारस, विष्णु पवित्रा रोपण, दामोदर द्वादशी, वैधृति पुण्य है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:15 तक, शुभ 10:54 से 12:33 तक, चर 3:50 से 5:29 तक, लाभ 5:29 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 5:57, सूर्यास्त 7:08

मेष
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

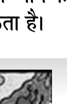

वृष
नवीन कार्यों में परेशानी हो सकती है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब होने का भय रहेगा। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

मिथुन
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

कर्क
व्यक्तिगत परेशानियां दूर होने लगेंगी। किसी भी कारण से बना हुआ मन का भय समाप्त होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। स्वास्थ्य में सुधार होगा।

सिंह
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। आज समय रचनात्मक कार्यों में व्यतीत होगा।

कन्या
घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है।

तुला
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

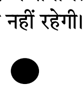

वृश्चिक
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य संबंधित मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।

धनु
घर-परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे।

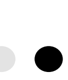

मकर
आज अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा। घर-परिवार के कारण भागदौड़ रहेगी। अनावश्यक धन खर्च होगा।

कुंभ
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों को मानसिक तनाव रहेगा।

मीन
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।